(d) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) Firm-wise/licence-wise statistics of imports are not maintained. In terms of the Export and Import Policy for 1992—97, import of all drugs other than those covered by the Negative List are allowed for import against specific licences and subject to conditions laid down.

(b) to (d) Adequate provisions are available in the Foreign Trade (Development and Regulation) Ordinance, 1992 and the Export and Import Policy to ensure proper utilisation of material imported against specific licences.

Recruitment process in Departments of Posts and Telecom

1153. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recruitment process is initiated directly by Department of Posts and Department of Telecom for Central Secretariat posts held by respective Departments;

(b) if so, the number of such posts in both Department, Cadre/Category-wise and the working strength therein as on the 30th June, 1992;

(c) whether back log vacancies of SC/ST in each cadre/category of posts mentioned in (a) above, have been filled up during IIIrd special Recruitment drive;

(d) if so, the number of vacancies filled up in each category during the period from January, 1991 to June, 1992;

(e) if not, the reasons therefor; and

(f) the number of backlog vacancies in these cadres/categories lying vacant as on the 30th June, 1992?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir. the Department of Posts & Telecommunications do not initiate the process of regular recruitment for posts of the Central Secretariat Service.

(b) to (f) As per Statement attached. (*See below*).

Statement

The number of sanctioned posts and the actual strength (including ad hoc promotions) in these two Departments as on 30th June, 1992 are indicated in the Table below:

Category	No. of sanctioned posts	Actual strength as on 30-6-92 (*ad hoc* promotions and the number of S. C. candidates included in such promotion's are shown in the bracket)
Group 'A'	25	23(4)
Group 'B'	600	599(228:SC-31)
Group 'C'	681	599(51:SC-11)

(c), (d) and (e) The backlog in regularv acancies upto 1988-89 has been reported to the Department of Personnel and Training who are the central recruitment authority for these posts of Central Secretariat Service. Nominations are yet to be received from them.

(f) The backlog of regular vacancies intimated to the Department of Personnel and Training is given in the Table below:

Category	S.C.	S.T.
Group 'B'	4	6
Group 'C'	1	5

टेलीफोन निदेशिकाओं के मुद्रण में विलंब

1154. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रकों और ठेके संबंधी समस्याओं के कारण गुजरात के कुछ क्षेत्रों में टेलीफोन निदेशिकाएं मुद्रित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो मुद्रकों और ठेकेदारों के विरुद्ध उनके नाम काली सूची में शामिल किए जाने सहित क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में नियमों की जानकारी न होने के कारण इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन निदेशिकाओं के मुद्रण में विलम्ब के लिए टेलीफोन अधिकारी भी जिम्मेदार थे; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

गुजरात के निम्नलिखित गौण स्विचन क्षेत्रों (एसएसए) के लिए टेलीफोन डायरेक्टरियों का नियमित मुद्रण नहीं किया जा रहा है :—

(i) भड़ौच

(ii) अमरेली

(iii) अहमदाबाद ग्रामीण।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभागेत्तर कर्मचारी (ई०डी०ई०) प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी

1155 **श्री राम नरेश यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागेत्तर कर्मचारी प्रणाली के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों की दशा को सुधारने के लिए कोई योजना तैयार की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) क्या सरकार ने विभागेत्तर प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है और यदि हां, तो उस समिति के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इसकी सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?